राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड
संयोजक बैंक ऑफ़ इंडिया
दिनांक 15.05.2019
स्थान होटल रेडिसन ब्लू

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड के 67 वीं त्रैमासिक बैठक का कार्यवृत
Minutes of the 67th Quarterly Meeting of SLBC, JHARKHAND

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड की 67वीं त्रैमासिक बैठक का आयोजन दिनांक 15.05.2019 को होटल रेडिसन ब्लू , रांची में किया गया।

इस बैठक के आरम्भ होने के पूर्व, एस.एल.बी.सी के मुख्य प्रबंधक श्री दीप शंकर ने बैठक में उपस्थित सदस्यों को जानकारी देते हुए कहा कि SLBC के पोर्टल में RBI के निर्देशानुसार बदलाव लाया जा रहा है । अतः बैंकों द्वारा उसी आधार में अपना डाटा पोर्टल में प्रविष्टि की जानी है । आगे उन्होंने, RBI द्वारा ध्यान में लाये गए मुद्दे पर कहा कि जिले से प्राप्त रिपोर्ट और SLBC से प्राप्त रिपोर्ट के ऋण जमा अनुपात डाटा में काफी भिन्नता पाई जाती है । यह बात 65 वीं SLBC के बैठक में एल.डी.एम. को विशेष रूप से बतलाया गया था, साथ ही उनसे कहा गया था कि अगले तिमाही से पत्येक तिमाही के समाप्त होने के पश्चात 25 दिनों के अन्दर बैंकों के नियंत्रक कार्यालयों से जिला-वार प्राप्त रिपोर्ट सभी एल.डी.एम. को मुहैया करा दिया जायेगा जिसे वे अपने जिले के DCC के बैठक में प्रस्तुत करें । दिसम्बर 2018 तिमाही से SLBC द्वारा सभी LDM को समय पर रिपोर्ट उपलब्ध भी कराया जा रहा है इसके बवजूद कुछ LDM अभी भी जिले के बैंकों से प्राप्त रिपोर्ट ही इन बैठकों में प्रस्तुत कर रहे हैं । उन्होंने पुनः सभी LDM से कहा कि तिमाही समाप्ति के 25 दिनों के अन्दर बैंकों के नियंत्रक कार्यालयों से जिला-वार प्राप्त रिपोर्ट सभी एल.डी.एम. को उपलब्ध करा दिया जाता है जिसे ही वे अपने जिले के DCC के बैठक में प्रस्तुत करें ताकि जिले एवं राज्य के रिपोर्ट में भिन्नता ना रहे। आगे उन्होंने कहा कि विजया बैंक एवं देना बैंकों का बैंक ऑफ़ बड़ोदा में विलय हो चूका है, साथ ही वनांचल ग्रामीण बैंक एवं झारखण्ड ग्रामीण बैंक का विलय हो झारखण्ड राज्य ग्रामीण बैंक का निर्माण हुआ है एवं प्रथम अप्रैल,2019 के तिथि से ये बैंक अस्तित्वा में आ चुके है; अतः 01.04.2019 से उनके सारे रिपोर्ट्स संयुक्त रूप से दिये जाने हैं ।

आगे उन्होंने जानकारी देते हुए बतलाया कि RBI के सलाह से 4 स्माल फ़ायनांस बैंको का डाटा भी 67 वीं SLBC के किताब में सम्मिलित किया गया है । आने वाले तिमाही से अन्य बैंकों की तरह ही सारा डाटा उन्हें SLBC के पोर्टल में डालना है जिसके लिए SLBC द्वारा इन्हें पोर्टल में डाटा प्रविष्टी का प्रवाधान कराने की प्रक्रिया की जा रही है ।

इसके पश्चात SLBC के महाप्रबंधक श्री चन्द्र शेखर सहाय को सभा को स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित किया गया ।

अपने संबोधन के आरम्भ में महाप्रबंधक श्री सहाय ने सभी मंचासीन गणमान्य अतिथियों, सभा में उपस्थित बैंकों एवं राज्य सरकार के सभी उच्च अधिकारीगण तथा अन्य विभागों से उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया । तत्पशचात उन्होंने पिछले तिमाही के दौरान राज्य के सभी बैकों तथा अन्य स्टेक होल्डरों, साथ ही विशेष कर सभी LDM को धन्यवाद देते हुए कहा कि इनके ही प्रयास से ही राज्य सभी वित्त अभियानों में सफल प्रदर्शन किया है, इसमें PMJJBY एवं PMSBY योजनाओं में राज्य पूरे देश में शीर्ष में रहा है । आगे उन्होंने कहा कि पिछले तिमाही में ही MSME SUPPORT एवं OUTREACH कार्यक्रम में हमारी उपलब्धि दिए गए लक्ष्य का 130% रहा है । PSB59MINS, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, NRLM आदी योजनाओं में भी बैंकों का उत्तकृष्ट प्रदर्शन रहा है । वर्ष 2018-19 के वार्षिक क्रेडिट प्लान पर 90.44 % की उपलब्धि रही है । कुछ क्षेत्र जैसे कृषि ऋण, रूपए कार्ड वितरण एवं activation, ऋण एवं जमा अनुपात, RSETI प्रशिक्षितों का क्रेडिट लिंकेज, एनपीए खातों के रिकवरी में बैंकों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है । इन पर आज के सभा में चिंतन किये जाने की आवश्यकता है।

अंत में उन्होंने सदन को आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य के समग्र विकास में बैंको का पूर्ण सहयोग रहेगा ।

SLBC के महाप्रबंधक श्री चन्द्र शेखर सहाय के स्वागत संबोधन के पश्चात मंचासीन अतिथियों का पुष्पगुछ दे कर स्वागत किया गया ।

इसके पश्चात् झारखण्ड सरकार के प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास, श्री अविनाश कुमार को सभा को संबोधन करने के लिए आमंत्रित किया गया । अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि चूँकि वे ग्रामीण विकास विभाग से हैं, ग्रामीणों को DBT के द्वारा उनके बचत खाते में दिए जाने वाले रकम के निकासी में होने वाले कठिनाइयो का जिक्र करना चाहते है । लाभुक के खाते में सीधे रकम पहुँचने के लिए DBT का आरम्भ किया गया । इस क्रिया द्वारा उनके खाते में रकम तो पहुच रही है लेकिन उनके अपने ही खाते से रकम की निकासी में कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है । इस विषय में उन्होंने कहा कि बैंकिंग के आन्तरिक कार्यप्रणाली के चलते इसमें बैंकों की अपनी कुछ बाध्यता हो सकती है लेकिन इसे सुगम बनाने की आवश्यकता पर उन्होंने जोर दिया । गढ़वा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रखण्ड कार्यालय के कर्मचारी एवं BC के मिली भगत से कई लाभुकों के खातों में छेड़-छाड़ कर रकम की अवैध निकासी कर लेने की मिली शिकायत का उन्होंने जिक्र किया । बचत खाता खोलने के वक्त खाताधारी के आवेदन में धोखे से अन्य व्यक्ति के अंगूठे का निशान ले लिया जाता है और इसी प्रकार आधार में भी आवेदक के स्थान पर अन्य व्यक्ति के अंगूठे का निशान ले लिया जाता है । इस तरह आवेदक अपने पहचान से वंचित हो जाता है और उनके खाते से रकम की अवैध निकासी कर ली जाती है । इस तरह के कई ऐसे धोखे के मामले सामने आए हैं जिसपर सुरक्षा के लिए मजबूती से कार्य किया जा रहा है । लेकिन इस तरह के धोखा-धड़ी में सुरक्षा के नाम पर बैंकों द्वारा खाता मेन्टेन करने की प्रक्रिया इतनी कठिन कर दी जाती है जिसपर व्यक्ति को खुद के पहचान में संदेह होने लगता है । जब एक खाते में आधार सीड कर दिया गया हो तो उस खाते में KYC की मांग करना बेमानी है । यह प्रक्रिया जटिल बनती जा रही है; इसपर

RBI को ध्यान दिए जाने की बात उन्होंने कही । ऋण के मामले में उन्होंने कहा कि ऋण के परिधि में एक व्यवसायी के अतिरिक्त एक नौकरी पेशा व्यक्ति भी आता है । लेकिन कुछ बैंकों द्वारा नौकरी पेशे व्यक्ति के पूरे रकम की अपने प्रतिभूति देने के बावजूद उनके विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र लाने की मांग की जाती है । आगे उन्होंने कहा कि NRLM में काफी अच्छा काम हुआ है लेकिन कुछ बैंकों के कार्य से उन्होंने असंतुष्ट होने की बात कही । सभी बैंकों को निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करनी चाहिए । RSETI के भवन निर्माण में आ रहे परेशानियों के सम्बन्ध उन्होंने लोहरदगा एवं रामगढ़ RSETI का जिक्र करते हुए कहा कि अगर निर्माण कार्य में कोई परेशानी आ रही है तो इसे राज्य सरकार के संज्ञान में लावें ।

इस संबोधन के पश्चात श्री के. के. खंडेलवाल, अतिरिक्त प्रधान सचिव, झारखण्ड सरकार को संबोधन के लिए आमंत्रित किया गया । अपने अभिभाषण में बैंकों के ऋण-जमा अनुपात में लगातार गिरावट पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में यह अनुपात 57.33% ही है जबकि राष्ट्रीय मानक 60% है , यह राज्य के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है । इसमें अनुपात के बेहतर बनाने के लिए बैंकों को अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता है । आगे उन्होंने कहा कि राज्य में 18 लाख किसानो को ही किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया है जबकि राज्य में इसके दुगना संख्या में किसानो को क्रेडिट कार्ड दिए जाने की पूर्ण संभावना है । बैंक आगे बढ़ कर इस योजना के तहत राज्य के सभी किसानो को यह कार्ड उपलब्ध कराएं । उन्होंने बैंकों से कहा कि बैंकों के शाखाओं में इस कार्ड के काफी आवेदन लंबित पड़े है, अगले खरीफ फसल के दौरान सबसे पहले इनका निष्पादन कर लें । इसके अलावे कृषि के अन्य क्षेत्र जैसे दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, कृषि यांत्रिकरण इत्यादि; साथही NABRD द्वारा संचालित एवं चिन्हित क्षेत्रिय विकास योजना को लागू किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया । आगे उन्होंने प्रधानमंत्री जन-धन खाता खोलने में बैंकों के सराहनीय कार्य की प्रशंसा की, साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में संतोष जनक कार्य नहीं होने के कारण इसमें जन जागरुकता लाने की आवश्यकता बताई ताकि राज्य के सभी वर्गों को इसका लाभ मिल सके । प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत उन्होंने कहा कि राज्य में इस योजना के अंतर्गत 39 लाख व्यक्तियों को विभिन्न कारोबार के लिए ऋण मुहैया कराया गया है । इस योजना का लाभ सुदूर इलाकों में भी पहुँचने की आवश्यकता है ताकि इससे लघु एवं कुटीर उद्योगों का सृजन हो सके एवं इसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिल सके और वे स्वावलंबी हो सके । "PSB Loans in 59 minutes" योजना पर उन्होंने कहा कि जबकि राज्य में 2353 लाभुकों को ऋण स्वीकृत किये गए हैं लेकिन 1207 लाभुकों को ही ऋण वितरण किया गया है, बाकी बचे लाभुकों को भी समय पर ऋण वितरण करने की जरुरत है । प्रधानमंत्री रोजगार कार्य्रम के तहत बैंक अपने लक्ष्य से काफी पीछे रह गए है । निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी बैंकों को अधिक प्रयास करने की जरुरत है । बैंको में NPA में काफी वृधी हुई है जो काफी चिंता का विषय है । SARFAESI एक्ट के तहत डिफाल्टर के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए सभी जिला पदाधिकरियों को निर्देश दिए जा चुके हैं । महिला स्वयं सहायता समूहों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बैंकों द्वारा 600 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध 700 करोड़ का ऋण दिया गया है, यह प्रशंसनीय है । 2019-20 के लिए 75000 समूहों को वित्त पोषण के लिए आवंटन का लक्ष्य रखा गया है । वर्ष के आरम्भ से ही इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बैंकों को प्रयास करने की जरुरत है । प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उन्होंने कहा कि बैंकों की उपलब्धि

इस योजना में काफी असंतोषजनक रहा है । इस विषय में बैंकों को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है ।

इस संबोधन के पश्चात NABARD के मुख्य महाप्रबंधक श्री ए. के. पाढ़ी को सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया । उन्होंने सभी बैंकर्स को 2018-19 वर्ष में उनके उपलब्धि के लिए प्रशंसा की । उन्होंने कहा कि 2018-19 कुल ऋण योजना 90% उपलब्धि रही है जो अपने आपमें एक अच्छी उपलब्धि है । लेकिन यह चिंता का विषय है कि वर्ष 2018-19 में प्राथमिकता के क्षेत्र में 73% उपलब्धि रही है जबकि 2017-18 में इसपर उपलब्धि 86% रही थी । वार्षिक ऋण योजना 2019-20 का जिक्र करते हुए कहा 2018-19 में ऋण में वार्षिक उपलब्धि 27027.28 करोड़ रूपये की रही है जबकि वर्ष 2019-20 के लिए 27202.96 करोड़ का लक्ष्य दिया गया है, इसमें सुधर की आवश्यकता है । आगे उन्होंने कहा कि बैंकों का ऋण जमा अनुपात घट कर 57% रह गया है अगर मान लिया जाय कि 2019-20 में कुल जमा में 10% की वृधि होती है और कुल ऋण में उपलब्धि पिछले वर्ष की ही रहती है तो ऋण – जमा अनुपात में और भी गिरावट होगी । इसपर पुनः विचार करने की आवश्यकता है । SLBC से उन्होंने कहा कि DDC एवं LDM को निर्देश दे कि वे अपने जिले के ACP पर पुनः विचार करें एवं आवश्यक सुधार करें । आगे उन्होंने KCC के सम्बन्ध में कहा कि राज्य में 39 लाख किसान हैं जबकि 17 लाख किसानो के पास ही KCC है । 17 लाख KCC में वर्ष 2018-19 में मात्र 6 लाख किसानो ने ही KCC का उपयोग किया है; अर्थात बाकी 11 लाख KCC निष्क्रिय रहे है । इसपर विचार करने की आवश्यकता है कि क्यों 11 लाख किसानो ने KCC का उपयोग नहीं किया है । उन्होंने पुनः ऋण जमा अनुपात में कहा कि राज्य के 16 जिलों में ऋण जमा अनुपात 40 % से कम रहा है । जिले के DCC के अंतर्गत CD रेशियो के सब-कमिटी में इसकी चर्चा की जानी चाहिए । SHG के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि राज्य में 2.55 लाख SHG समूह है जिसमे से 1.5 लाख समूहों का ही क्रेडिट लिंकेज हुआ है । ऐसे SHG का चिन्हित किया जाना है जिनका अभी तक क्रेडिट लिंकेज नहीं हो पाया है, उनका क्रेडिट लिंकेजे किये जाने के लिए NRLM एवं JSLPS को प्रयास करना है । JLG को ऋण मुहैया कराये जाने की बात उन्होने कही जिसमे राज्य में बैंको द्वारा CNT एक्ट के कारण संपार्श्विक प्रतिभूति (collateral security) प्राप्त करने में आ रही परेशानी की बात कही जा रही है । इस वर्ष के लिए राज्य को 10,000 Joint liabilities group बनाने का टारगेट दिया गया है जिसे NABRD द्वारा बैंक-वार टारगेट दिया जा चूका है । वित्त-स्केल की बात करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि ऋण के लिए जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा जिले में विभिन्न फसल के लिए वित्त-स्केल निर्धारित की जाती है जिसके आधार पर बैंकों द्वारा कृषक को ऋण दिया जाता है । वर्ष 2019-20 के लिए जिलों में जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित वित्त-स्केल अभी तक 17 जिलों के LDM द्वारा ही दिया गया है । उन्होंने राज्य के कृषि विभाग से कहा कि उपयुक्त समय पर जिले के लिए वित्त-स्केल बनायें ताकि समय पर बैंकों को कृषि ऋण वितरण करने के लिए इसे मुहैया कराया जा सके । विभिन्न जिलों द्वारा बनाये गये वित्त-स्केल में काफी भिन्नता पाई जाती है । इसके लिए राज्य कृषि विभाग विभिन्न जिलों के तकनीकी समिति द्वारा बनाये गए कृषि वित्त-स्केल पर विशेष ध्यान दें ताकी उनमे काफी भिन्नता ना रहे । उन्होंने आगे कहा भारत सरकार द्वारा निर्देश दिया गया है कि राज्य मत्स्य पालन एवं दुग्ध विकास का भी वित्त-स्केल अन्य फसलों के साथ कृषि ऋण के

लिए निर्धारित किया जाना है जिसकी जानकारी सभी जिलों को दे दी गयी है लेकिन कई जिलों ने मत्स्य पालन एवं दुग्ध विकास का वित्त-स्केल नहीं बनाया है । प्रधानमंत्री फसल बीमा पर उन्होंने कहा कि यह विचित्र है कि राज्य में गत वर्ष 12 लाख गैर-कर्जदार कृषकों ने फसल बीमा कराया जबकि बैंको से फसल ऋण लिए मात्र 3.3 लाख कृषकों ने ही फसल बिमा कराया साथ ही गत वर्ष में बैंकों द्वारा लगभग 6 लाख कृषकों को फसल ऋण दिया गया है । इससे प्रतीत होता है कि 2.6 लाख कृषकों का फसल बीमा नहीं हो पाया है । भारत सरकार के निदेशानुसार प्रत्येक कृषक का फसल बीमा निश्चित होना है । सभी बैंकों को इसपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । अपने संबोधन को जारी रखते हुए उन्होंने "E-Shakti" जो स्वयं सहायता समूह के लिए है जिसके अंतर्गत समूहों का बैंकों के सहायता से डिजिटलीकरण किया जाना है, अब तक 7 जिलों में 21000 समूहों का डिजिटलीकरण किया जा चूका है एवं अगले वर्ष 6 अन्य जिलों में भी समूहों का डिजिटलीकरण किया जाना है । इस डीजीटाईजेसन से निर्णय लिया जा सकेगा कि समूह की क्या स्थिति है एवं समूह को कितनी वित्तीय सहायता दी जा सकती है । इसके पश्चात उन्होंने Farmers Producer Organisation की संछिप्त जानकारी दी । क्षेत्र विकास योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा राज्य में चयनित 6 गतिविधियों का क्षेत्र वार इनके संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जिला वार / बैंक वार/ शाखा वार लक्ष्य वितरित कर दिया गया है । इसका हरेक DCC के विभिन्न बैठकों में एक मुख्य एजेंडा के रूप में चर्चा किया जाना है । जिला के बैकवार इसकी उपलब्धि LDM द्वारा SLBC को दी जानी है । उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि Financial Inclusion के अंतर्गत बैंकों को तकनीकी सहायता दिए जाने के लिए 8.3 करोड़ रूपये अनुदान के रूप में NABARD को उपलब्ध है ।

इस संबोधन के पश्चात श्री संजीव दयाल , भारतीय रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक को सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया । अपने संबोधन में उन्होंने बैंकों के महत्वपूर्ण संकेत के ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि वर्ष दर वर्ष में ऋण में 11.75 % एवं जमा में 10.08 % की वृधि हुई है । लेकिन CD ratio में गिरावट आयी है जो वर्ष दर वर्ष में 60.31 % से घट कर 57.33 % हो गई है । इसका मुख्य कारण Place of utilization एवं RIDF में 4492 करोड़ के गिरावट हो सकता है । साथ ही कुछ बड़े बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, बैंक ऑफ़ इंडिया, यूनियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक के कुल ऋण पिछले तिमाही के तुलना में नीचे चला गया है । उन्होंने कहा कि पिछले तिमाही एवं वर्तमान तिमाही के डाटा देखने में महसूस होता है कि बैंकों के रिपोर्टिंग में कहीं ना कहीं चुक हो रही है । इसे पुनः जाँच करने की जरुरत है । कुल कृषि ऋण में वर्ष दर वर्ष आधार पर 10.22 % बढ़ोतरी हुई है । वर्तमान 2018-19 वर्ष में कुल ऋण के अंतर्गत कृषि ऋण में उपलब्धि प्रतिशत पिछले वर्ष 2017-18 की तुलना में कम रहा है । आगे उन्होंने बैंकों को ऋण में 90 % की उपलब्धि पर बधाई दी साथ ही उन्होंने कहा कि गैर प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण में लक्ष्य से अधिक की उपलब्धि हुई है लेकिन प्राथमिकता वाले क्षेत्र में अपेक्षाकृत उपलब्धि नहीं रही है । उन्होंने बैंको से कहा कि गैर प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण के स्थान पर प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । उन्होंने बैंकों में लगातार बढ़ते हुए NPA पर चिंता व्यक्त किया और कहा कि आज राज्य के बैंकों में कुल 5711.86 करोड़ रूपये का NPA हो गया है । उन्होंने राज्य सरकार से NPA वसूली में

Dedicated Certificate Officer के नियुक्ति के बात कही । उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के 2015 में जारी परिपत्र का जिक्र करते हुए कहा कि Negotiable Warehouse रसीद द्वारा दिए गए वर्तमान ऋण का डाटा बैंकों द्वारा जिलावार दिया जाना है । लेकिन SLBC द्वारा यह डाटा अभी तक नहीं दिया जा रहा है । वित्तीय समावेशन में उन्होंने विभिन्न ग्रामों में बैंकिंग सुविधा से सम्बंधित डाटा का जिक्र करते हुए कहा कि 2000 जनसंख्या से नीचे एवं 5000 जनसंख्या से अधिक का डाटा उन्हें SLBC द्वारा दे दिया गया है परन्तु 2000 से 5000 जनसंख्या वाले ग्रामो के इस सम्बंधित डाटा अप्राप्त है । SLBC द्वारा जानकारी दी गई है कि यह डाटा सिर्फ देवघर जिले से अप्राप्त है । उन्होंने देवघर जिले के LDM से कहा कि शीघ्र यह डाटा SLBC को उपलब्ध कराएं । आगे उन्होंने कहा कि पिछले SLBC के तिमाही बैठक में कहा गया था कि अगले प्रत्येक तिमाही बैठक से अवैध संस्थानों से चलाये जा रहे अवैध बैंकिंग गतिविधि एवं साइबर क्राइम से सम्बंधित जानकारी पर चर्चा किये जाने के लिए एक एजेंडा होनी चाहिए । उन्होंने सभी बैंकों से कहा कि इस तरह की कोई सुचना मिलती है तो इसकी जानकारी SLBC को दें ताकि इन जानकारियों पर बैठक में चर्चा की जा सके और समय पर इन अवैध गतिविधिओं में अंकुश लगाया जा सके । उन्होंने LDMs को संबोधित करते हुए कहा कि BLBC/ DLCC की बैठक समय पर करें और बैठक की पूर्व सुचना RBI को भी दें ताकि RBI का कोई एक प्रतिनिधि इसमें शामिल हो सके । BC का चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बैंकों को ध्यान देना है कि उनके BC निर्धारित स्थान में उपस्थित रहते है या नहीं ?

श्री संजीव दयाल, महाप्रबंधक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभा को संबोधन के पश्चात बैठक का व्यवसाय सत्र आरम्भ किया गया ।

व्यवसाय सत्र)Business Session) :

SLBC के मुख्य प्रबंधक श्री दीप शंकर द्वारा व्यवसायिक सत्र की कार्यवाही शुरू करते हुए सबसे पहले दिनांक 15.02.2019 को आयोजित 66वीं सभा संपुष्टि की कार्यवृत के बैठक SLBC | गयी करायी द्वारा

तत्पश्चात श्री दीप शंकर द्वारा एसएलबीसी की 67वीं बैठक में चर्चा के लिए निर्धारित एजेंडा क्रमवार निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया :

<u>डेडिकेटेड सर्टिफिकेट अधिकारी</u>

डेडिकेटेड सर्टिफिकेट अधिकारी के नियुक्ति तथा कार्यालीय खर्च के मुद्दे पर बैंकों ने ऋण वसूली का 5% सरकार को देने का प्रस्ताव रखा था जिस पर राज्य सरकार ने प्राथमिक सहमति जताई है। एसएलबीसी ने इस संबंध में मध्य प्रदेश का नियमावली मंगवाया है। अन्य राज्यों के नियमावली के लिए एसएलबीसी एवं OSD,BANKING श्री बिनोद सिन्हा को प्रयास करना है।

दिनांक खंडेलवाल के के श्री में संबंध इस को 2019 मई 23,अपर वित्त सचिव ,वित्त विभाग की अध्यक्षता में एक बैठक रखी गई है। इस संबंध में श्री के के खंडेलवाल ने संयुक्त सचिव ,भूमि एवं राजस्व विभाग से इस से संबन्धित modalities पर कारवाई करने को कहा।

बैंको को भवन निर्माण हेतु जमीन का आवंटन

इस संबंध में श्री दीप शंकर ने बताया की जमीन के मूल्य में सरकार द्वारा अप्रत्याशित वृद्धि हुयी है।इस मुद्दे पर हुई श्री के के सोन ,सचिव राजस्व विभाग ने पूर्व में बताया था कि पूर्व में Non Commercial Rate पर समिति ने जमीन का मूल्य निर्धारित किया था जिसको बाद में Commercial Rate पर संशोधित कर बैंको को प्रेषित किया गया । उन्होने एक बार फिर से तय रेट पर calculation check करने की बात की और कहा यदि मूल्य सही पाया जाता है तो वैसे बैंक जिनको भूमि आवंटित किया गया है उनको जमीन खरीदने या ना खरीदने संबन्धित त्वरित निर्णय ले कर सरकार को सूचित करना है। सभा में संयुक्त सचिव, भूमि एवं राजस्व विभाग ने यह भी बताया गया कि एसएलबीसी के नाम से आवंटित भूमि को बैंक ऑफ इंडिया के नाम पर आवंटित कर दिया गया है और इस संबंध में पत्र DC,RANCHI को भेज दिया गया है ।

गैर निष्पादनीय आस्तियां

राज्य सरकार से लंबित पड़े त्वरित के SARFAESI cases एवं certificate cases । गया किया आग्रह का निष्पादनसाथ ही सभी बैंकों से भी यह आग्रह किया गया कि विभिन्न जिलों में पास के जिलाधिकारियों लिए के physical possession अंतर्गत के SARFAESI की cases लंबित पड़ेजानकारी पूर्ण विवरण के साथ उन्हे सीधे या SLBC नियमित उपलब्ध करायी जाये जिसे राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारीयों के साथ । सके जा किया shareश्री के के खंडेलवाल अपर, मुख्य सचिव वित्त , विभाग ने निर्देश दिया की सभी बैंक जिला स्तर पर लम्बे समय से लंबित बड़ी राशी वाले आवेदनों की सूची अविलम्बSLBC को भेजे, इन बड़े खातों को अगले जिलाधिकारियों के बैठक में रिव्यु किया जाएगा ।

श्री दीप शंकर ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आग्रह किया कि राज्य स्तर पर उनके बैंक का कुल एनपीए का आंकड़ा एसएलबीसी पोर्टल पर दिया जाये जिससे सएलबीसी राज्य के सकल एनपीए के आंकड़े को सही ढंग से विभिन्न फोरम पर रख पाएगा।

अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदत्त ऋण

श्री दीप शंकर ,मुख्य प्रबंधक ने झारखण्ड राज्य में बैंकों द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग को दिए गए ऋण कुल ऋण का 11.55% निर्धारित मानक 15% से कम होने की बात कही ।राज्य में इसमें बैंकों द्वारा सुधार लाने की आवश्यकता है) ।**Action : सभी बैंक(**

सभी बैंको के महत्वपूर्ण संकेतक

इस विषय पर सभा को बताया गया कि Y-o-Y basis पर की जाने वाली तुलना के साथ साथ SLBC द्वारा राज्य में पिछले तिमाही की तुलना में हुई वृद्धि/ह्रास की जानकारी भी देने का प्रयास किया गया है और अगली बैठक से इसकी रिपोर्टिंग में और भी आवश्यक संशोधन करने का प्रयास किया जायेगा । महिलाओं एवं अल्पसंख्यक समुदायों को दिये जाने वाले ऋण से संबंधित

रिपोर्टिंग में कई बैंको द्वारा काफी variation किये जाने की तरफ सभा का ध्यान आकृष्ट कराया गया । साथ ही कई बैंक जिनके कारण कई आंकड़ों में त्रुटी आई थी उनको सभा के माध्यम से आंकड़ों को त्रुटिहीन रखने का आग्रह किया गया और सभी से इस पर ध्यान देने की अपील की गई । **(Action: SLBC, सभी बैंक)**

वार्षिक ऋण योजना के आधार पर वर्ष 2018- की 19उपलब्धि की समीक्षा

इस विषय पर मुख्य प्रबन्धक श्री दीप शंकर ने जानकारी देते हुए बतलाया कि reporting quarter के दौरान बैंको ने ACP target के विरुद्ध लगभग 90% achievement कर लिया है । राज्य का CD ratio इस तिमाही 60% के मानक से 3% कम हो गया है। **सभा को बताया गया कि मार्च 2019 quarter के दौरान राज्य में बैंको द्वारा दर्ज की गयी incremental CD ratio 97.62 % है ।** कई sectors में बैंको द्वारा reporting में की गयी खामियों की चर्चा की गयी और उनसे आने वाले समय में reporting में आवश्यक सुधार किये जाने का आग्रह किया गया । सभा को बैंक की शाखाओं की संख्या के आधार पर की गयी रैंकिंग की जानकारी दी गयी । राज्य में बैंकों के Overall प्रदर्शन के आधार पर दो सर्वश्रेष्ठ बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं बैंक ऑफ इंडिया को सम्मानित किया गया।

(Action: सभी बैंक एवं SLBC)

वित्तीय वर्ष 2019-20 के ACP TARGET निर्धारण में एसएलबीसी द्वारा त्रुटि पाई गई है। कई जिलों में लक्ष्य पिछले वित्तीय वर्ष के उपलब्धि से भी कम पाया गया है।श्री के के खंडेलवाल ने इस पर गहरी चिंता व्यक्त की। श्री दीप शंकर से सदन को बताया कि सभी एलडीएम अपने लक्ष्य को PLP के आधार पर पुन:निर्धारण कर DLCC में approve करा कर एसएलबीसी को अविलंब भेजे दें ताकि ACP निर्धारण की प्रक्रिया पुनः की जा सके ।श्री आर आर तिवारी,स.म.प्र.,RBI ने सदन को बताया कि नए LBS योजना के तहत ACP लक्ष्य को बैंक के कॉर्पोरेट टार्गेट के समतुल्य करने का प्रयास होना चाहिए। **(सभी LDM)**

श्री दीप शंकर ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए PLP निर्धारण में प्रखण्ड स्तर पर बैंक शाखाओं की भागीदारी सुनिश्चित कराने का आग्रह नाबार्ड से किया। उन्होने कहा कि शाखा स्तर की भागीदारी से PLP PREPARATION ज्यादा प्रभावी हो पाएगा। **(नाबार्ड)**

कई जिलों एवं बैंक का ACP TARGET के विरुद्ध उपलब्धि 75% से कम पाई गयी है। इन बैंक एवं जिलों में नए strategies बना कर इस वित्तीय वर्ष में लक्ष्य प्राप्ति पर कार्य करने को कहा गया है। **(सभी बैंक/एलडीएम)**

जिन जिलों का CD अनुपात 40% से कम है उनके एलडीएम को स्पेशल DCC का गठन करने को कहा गया। श्री दीप शंकर ने कहा कि ऐसे जिलों मे MONITORABLE ACTION PLAN बना कर हर महीने उस प्लान का review जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होनी चाहिए।
(सभी एलडीएम)

कृषि ऋण एवं किसान क्रेडिट कार्ड

इस पर चर्चा करते हुए सभा को बताया गया कि कृषि क्षेत्र में इस वित्तीय वर्ष में 3824.82 करोड़ रु का संवितरण हुआ है जो कि कुल लक्ष्य का 46% ही है, यह अतिचिंतनीय है। इसमें KCC में रु 2396.22 करोड़ का संवितरण हुआ है। यह आंकड़ा उत्साहवर्धक कतई नहीं है। डेयरी के अंतर्गत लंबित आवेदनो को तुरंत निष्पादित करते हुए योजना अंतर्गत दिये जा रहे अनुदान के लिए पोर्टल पर तुरंत आवेदन करने को कहा गया।

श्री दीप शंकर ने कहा कि एरिया बेस्ड डेवलपमेंट स्कीम के मुद्दे पर सब कमिटी में काफी चर्चा हुई है । बैठक में इस निष्कर्ष पर पहुँचा गया कि इस विषय पर कृषि उप समिति में चर्चा की जाए। सभी एलडीएम को पुनः निर्देश दिया गया कि एरिया बेस्ड स्कीम को DLCC कि बैठक में अनिवार्य रूप से शामिल करें। एरिया बेस्ड स्कीम से संबन्धित एक फ़ारमैट सभी एलडीएम को दी गई है। उस प्रारूप में डाटा सभी बैंक से ले कर नाबार्ड एवं एसएलबीसी को प्रेषित करे। आने वाली बैठकों में इस एरिया बेस्ड स्कीम के आंकड़े को एसएलबीसी Book में लाया जाएगा। (**Action: बैंक एवं एलडीएम/नाबार्ड/एसएलबीसी)**

Doubling of Farmers income-नए LBS के आधार पर आने वाले हर बैठक में Doubling of Farmers income एक महत्वपूर्ण अजेंडा के रूप में शामिल किया जाएगा। **(SLBC)**

श्री रमेश घोलप, निदेशक, कृषि विभाग ने सदन को बताया कि समय से केसीसी ऋण अदायगी करने वाले किसानों को केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली 3% interest subvention के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 3% Interest Subvention दिया जा रहा है। परंतु इस संदर्भ में किसी भी तरह का क्लेम किसी भी बैंक द्वारा नहीं किया जा रहा है। उन्होने एलडीएम को ज़िले स्तर कि बैठक में भी चर्चा करने को कहा। एसबीआई के AGM, श्री एस ॰ के॰ सिन्हा ने कहा कि एसबीआई ने क्लेम झारखंड स्टेट cooperative बैंक को भेजा है और यह लंबे समय से लंबित है। श्री के के खंडेलवाल ने झारखंड स्टेट cooperative बैंक के प्रतिनिधि को निर्देश दिया कि इसका निपटारा जल्द करें। **(सभी बैंक/JSCB)**

श्री के के खड़ेलवाल ने सभी एलडीएम से कहा की कुल कितने आवेदन केसीसी के बैंक को भेजे जा रहे है इस आंकड़े को इकट्ठा करें एवं लंबित आवेदन का निपटारा करे। उन्होने निदेशक, कृषि विभाग से भी पूरे राज्य में केसीसी आवेदनों के सृजित एवं लंबित आवेदनों का आंकड़ा रखने को कहा । उन्होने कहा कि पूर्व में जिला स्तर पर यह कार्य नियमित तौर पर होता था। उसको पुनः शुरू किया जाए। **(सभी एलडीएम/ कृषि विभाग-राज्य सरकार)**

<u>राज्य में घोषित सुखाड़ के तहत affected किसानों को Relief Measures प्रदान करना</u>

झारखंड में सुखाड़ घोषणा के उपरांत सभी बैंक को अधिसूचना की प्रति 30-11-2018 को आरबीआई के संबन्धित circular के साथ एसएलबीसी द्वारा भेज दी गयी है।RBI ने 14 मई को सभी बैंक को मेल भेज कर निर्देश दिया है कि RBI के डेडिकेटेड पोर्टल पर हर महीने की 10 तारीख तक किसानों को जो Relief Measures MASTER DIRECTION के अनुसार दिए गए है उसके आंकड़े अपलोड करने है। सभी बैंक से आग्रह किया गया कि इस

निर्देश का पालन करें।
(ACTION: सभी बैंक)

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना

श्री दीप शंकर ने बताया कि प्रधान मंत्री मुद्रा योजना का एसएलबीसी पोर्टल पर बैंकों द्वारा अपलोड किया गया डाटा एवं मुद्रा पोर्टल पर बैंक के हेड ऑफिस द्वारा डाले गए डाटा में काफी अंतर पाया गया है। इस तरह विसंगति को बैंकों द्वारा दूर किया जाना चाहिए। आने वाले समय में एसएलबीसी मुद्रा पोर्टल पर उपलब्ध डाटा को authentic डाटा के रूप में लेने की बात कही।
(ACTION: सभी बैंक)

विद्या लक्ष्मी पोर्टल

सचिव, मानव संसाधन मंत्रालय , भारत सरकार ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है कि हमारे राज्य से संबन्धित हजारों शिक्षा ऋण के आवेदन विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर निष्पादन के लिए लंबित है। श्री दीप शंकर ने सभी नियंत्रक प्रमुखों का इस ओर ध्यान आकृष्ट करवाते हुए कहा कि लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन किया जाए एवं बिना वैद्य कारणों के आवेदनों को अस्वीकृत नहीं करे। **(ACTION: सभी बैंक)**

एसएचजी महिलाओं के वित्त पोषण हेतु योजना

SHG की SLBC SUB-COMMITTEE के बैठक में इस वित्तीय वर्ष के अन्दर SHG CREDIT LINKAGE का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । इस वित्तीय वर्ष में कुल 75000 एसएचजी ग्रुप को 1000 करोड़ ऋण वितरित करने का लक्ष्य दिया गया है। इस लक्ष्य में FRESH SANCTION एवं ENHANCEMENT दोनों को शामिल किया गया है।अगली तिमाही से तीन अलग अलग डाटा ना लेकर आजीविका पोर्टल के डाटा को ही लिया जाएगा। सभी बैंक से आग्रह आग्रह किया गया कि आजीविका पोर्टल से डाटा लेकर एसएलबीसी पोर्टल में डाले। जेएसएलपीएस से भी आग्रह किया गया कि वो आजीविका पोर्टल के आंकड़े के अनुसार ही review करे। साथ ही सभी बैंको से लंबित आवेदनों को निष्पादित करने को कहा गया।
(ACTION: सभी बैंक)

वित्तीय समावेशन/प्रधानमंत्री जन धन योजना

श्री मदनेश मिश्रा, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग भारत सरकार ने पिछले बैठक मे कहा था कि राज्य में प्रतिदिन 50 से कम transaction करने वाले BC की संख्या काफी अधिक है अर्थात कई BC का कार्य संतोषजनक नहीं है, जिसे बढ़ाये जाने की आवश्यकता है ।श्री दीप शंकर इस दिशा में बैंको को विशेष प्रयास करने को कहा।
(Action:सभी संबंधित बैंक)

PMEGP/PMAY/NULM

SLBC द्वारा सभी बैंको से इन schemes के तहत लंबित आवेदनों के अतिशीघ्र निष्पादन करने का आग्रह किया गया । **(Action: सभी बैंक)**

RSETI/FLCC

श्री अविनाश कुमार, प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ने कहा राज्य में बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित RSETI के भवन निर्माण का कार्य संतोषजनक है परंतु SBI द्वारा RSETI के भवन निर्माण का कार्य असंतोषजनक है । इनके निर्माण कार्य मे और गति लाने की आवश्यकता है। उन्होने रामगढ RSETI के भवन निर्माण के संदर्भ में BOI को निर्णय जल्द लेने को कहा। श्री दीप शंकर ने कहा कि **RSETI trainees** भविष्य के अच्छे ऋण लाभूक/व्यवसायी है अतः उन्हे समुचित ट्रेनिंग के उपरांत ऋण आवेदन ले कर संबन्धित बैंकों को भेजें ।
श्री सतेन्द्र सिंह ने **PNB** के प्रतिनिधि से रामगढ RSETI के बारे में पूछा। पीएनबी के सहायक महाप्रबंधक ने कहा कि जमीन का आकार ही समस्या है। सही आकार के जमीन मिलने पर PNB RSETI निर्माण के बारे में निर्णय ले सकता है । हालांकि उन्होने यह भी कहा कि बैंक ऑफ इंडिया ने रामगढ RSETI लेने में हामी भरी है और मामला बैंक ऑफ इंडिया के समक्ष ही लंबित है।
(Action: BOI, सभी बैंक , RSETI Directors, JSLPS)

आर.बी.आई. के महाप्रबंधक श्री संजीव दयाल ने पिछले बैठक में कहा था कि प्रत्येक एफ.एल.सी. के कार्य के लिए कौंसलर की नियुक्ति होनी चाहिए ।इस सन्दर्भ में झारखण्ड ग्रामीण बैंक ने बताया था कि उन्होंने नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर ली है ।अब चूँकि JGB विलय होकर JRGB हो गया है तो उनके चेयरमैन ,श्री जोड़े से आग्रह किया गया कि नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी कर लें । **(Action : JRGB)**

विविध कार्यसूची

1.ROADMAP for villages having population between 2000 and 5000- राज्य में 2000 से 5000 तक की जनसंख्या वाले गाँव को बैंकिंग कवरेज सुनिश्चित करने के लिए एक Roadmap की आवश्यकता है। इसके लिए इस श्रेणी के सभी गाँव चिन्हित कर बैंकिंग सुविधा कवरेज सुनिश्चित करने हेतु सूची तैयार कर राज्य के सभी एलडीएम द्वारा (केवल देवघर को छोड़कर) सूची भेज दी है। LDM देवघर से आग्रह है कि सूची से संबन्धित आंकड़े जल्द एसएलबीसी को अद्यतन कारवाई के लिए प्रेषित करे।**(Action: LDM देवघर)**

2. DFS द्वारा identified 440 centres पर BC की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में हुई चर्चा के दौरान VGB के द्वारा वैसे 11 centres जिनपर या तो connectivity issue अथवा किसी अन्य बैंक का SSA होने के कारण BC नियुक्त नहीं किया गया है , पर BC नियुक्त किये जाने की बात कही गयी | अभी भी इन 11 centres पर BC नियुक्त नहीं हुए है । CHAIRMAN ,JRGB से आग्रह किया गया कि इन 11 centres पर BC नियुक्त कर लिए जाए। **(Action: VGB)**

3. सभी LDMs से पूर्व के बैठक में आग्रह किया गया कि राज्य के सभी 4178 SSA को पुनः नए सिरे से बैंको को allot किये जाने की आवश्यकता है और इस सम्बन्ध में देवघर और गढ़वा जिले से सूची नहीं आया है।सभी एलडीएम से यह भी आग्रह किया गया कि इस सूची को बीएलबीसी में पारित करा कर जिले के सभी बैंक को ससमय प्रेषित कर दे। **(Action: सभी LDMs)**

4. BLBC बैठक- श्री दीप शंकर ने बताया की पिछले एसएलबीसी बैठक में श्री मदनेश मिश्रा ने बीएलबीसी बैठक को एसएलबीसी मीटिंग में एक **agenda** के रूप में शामिल करने को कहा।उन्होने एक फ़ारमैट तैयार कर जिसमे की प्रखण्ड वार बैठक की तिथि, प्रखण्ड में कुल बैंक शाखाओं की संख्या, उपस्थित बैंक की संख्या को संलग्न करने को कहा। सभी एलडीएम को हर तिमाही अपने सभी प्रखण्ड में हुये बीएलबीसी बैठक की जानकारी एसएलबीसी को समयसीमा में उपलब्ध करनी है। **(Action:SLBC,सभी बैंक एवं LDMs)**

5. श्री के के खंडेलवाल ने सभी एलडीएम को ज़िला स्तर पर बैंक से सहयोग ना मिलने पर तुरंत इसकी शिकायत एसएलबीसी से करने को कहा। उन्होने एसएलबीसी से ऐसी शिकायत पर तुरंत कारवाई करने को कहा । **(Action:SLBC,सभी बैंक एवं LDMs)**

6. श्री के के खड़ेलवाल ने एलडीएम से कहा कि जिला में ऋण प्रवाह की ज़िम्मेदारी एलडीएम पर है। उन्हें ऋण प्रवाह के लिए सक्रिय कदम उठाना चाहिए। **(Action: सभी LDM)**

7. **STEERING COMMITTEE** -किसी भी नए अजेंडा को एसएलबीसी की त्रैमासिक बैठक में शामिल करने से पहले उस अजेंडा को STEERING COMMITTEE में चर्चा की जाएगी। समिति के सहमति के उपरांत ही नए अजेंडा को बैठक के चर्चा में शामिल किया जाएगा। **(Action: सभी सदस्य)**

8. **आधार एवं मोबाइल सीडिंग** - श्री सतेन्द्र सिंह, सचिव व्यय ने कहा कि जिन खातों में आधार एवं मोबाइल सीडिंग नहीं हुई है, उन खातों को शाखा वार चिन्हित कर drive चला कर आधार एवं मोबाइल सीडिंग कर लिया जाना चाहिए। सभी बैंक के नियंत्रक प्रमुख से इसका review करने को कहा गया।

9. **पेंशन से संबन्धित आंकड़े** - श्री सतेन्द्र सिंह ,सचिव व्यय ने कहा कि पेंशन से संबन्धित आंकड़े राज्य सरकार द्वारा मांगा गया था,परंतु कई बैंक ने यह डाटा राज्य सरकार को नहीं भेजा है। सभी बैंक जिनके समक्ष ये आंकड़े लंबित उन्हें तत्काल सरकार को यह डाटा उपलब्ध कराना है।

10. **अटल पेंशन योजना-** PFRDA ने राज्य में अटल पेंशन योजना के तहत अच्छे प्रदर्शन के लिए विभिन्न बैंक की शाखाओं को मोमेंटों प्रदान किया गया ।

11 . एसएचजी में अच्छे प्रदर्शन के लिए बैंक ऑफ इंडिया,स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक (JGB एवं VGB के विलय के उपरांत) , PNB, यूनियन बैंक ,लातेहार,पलामू एवं साहिबगंज को PRIZE दिया गया।

12. बैंकों को प्रदर्शन के लिए प्रशस्ति पत्र- राज्य में बैंकों के Overall प्रदर्शन के आधार पर दो

सर्वश्रेष्ठ बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं बैंक ऑफ इंडिया को सम्मानित किया गया तथा INCREMENAL PERFORMANCE के आधार पर केनरा बैंक तथा इलाहाबाद बैंक को प्रशस्ति पत्र दिया गया। आने वाली हर बैठक में यह प्रोत्साहन का कार्यक्रम जारी रहेगा।

अंत में SLBC,JHARKHANDके DGM श्री विंसेंट लकड़ा ने उपस्थित गणमान्य विशिष्ट अतिथियों एवं उपस्थित सभी लोगों को 67वीं SLBC को सुचारु संचालन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होने सभी LDM एवं बैंक से आग्रह किया कि सभा में जितने सुझाव आए है उनको अगर धरातल पर लाया जाए तो स्थिति और भी बेहतर हो सकती है।उन्होने अंत में सभी हितधारकों से केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं में बढ़-चढ़ कर भाग लेने का आग्रह किया ताकि राज्य का समुचित विकास हो सके।

(विन्सेंट लकड़ा)
उप महाप्रबंधक, रा.स्त.बै.स.